Samyak
An Institute For Civil Services

Daily Mains Writing – 10 April

The RBI's 6 -member Monetary Policy Committee (MPC) recently decided to cut the repo rate by 25 basis points to 6%. Discuss the impact of repo rate cuts on economic growth and inflation. (150 words)

Repo rate (Repurchase Agreement Rate) is the interest rate at which commercial banks borrow money from the central bank. The RBI's MPC recently cut the repo rate to 6% which will encourage borrowing and spending thus improving the overall economy.

Implications of Repo Rate Cut

- **Economic Growth**:
  - Lower borrowing costs encourage business expansion and investment, leading to higher production and job creation.
  - Reduced interest rates make loans cheaper, which lowers EMIs and boosts borrowing and spending.
- **Financial Markets**:
  - Banks may lower interest rates on savings and fixed deposits, making savings less attractive.
  - Consumers may be driven towards stocks, mutual funds, or real estate as alternative investment options.
- **Export Competitiveness**:
  - Lower repo rate can reduce investment returns, leading to capital outflows.
  - A weaker currency may raise import costs but improve export competitiveness.
- **Inflation**:
  - Increased spending from lower rates could drive up prices and inflation.
  - Inflation may exceed the RBI's target of 4% within a band of +/- 2%.

The change comes amid global economic uncertainty, particularly due to trade frictions and tariffs imposed by the US. It is aimed to set the overall interest rate environment in the banking system and broader economy.

Samyak An Institute For Civil Services

RBI की 6-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6% करने का निर्णय लिया। आर्थिक विकास एवं मुद्रास्फीति पर रेपो दर में कटौती के प्रभाव पर चर्चा करें। (150 शब्द)

रेपो दर (पुनर्खरीद समझौता दर) वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से पैसे ऋण के रूप में लेते हैं। RBI की MPC ने हाल ही में रेपो दर को घटाकर 6% कर दिया है जो ऋण लेने और खर्च करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेगा जिससे समग्र अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

रेपो दर में कटौती के निहितार्थ

- **आर्थिक वृद्धि**:
  - कम ऋण लागत व्यवसाय विस्तार एवं निवेश को प्रोत्साहित करती है, जिससे उत्पादन एवं रोजगार सृजन बढ़ता है।
  - कम ब्याज दरें ऋण को सस्ता बनाती हैं, जिससे ईएमआई कम होती है और ऋण लेने एवं खर्च करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है।
- **आर्थिक बाज़ार**:
  - बैंक बचत और सावधि जमा पर ब्याज दरों को कम कर सकते हैं, जिससे बचत कम आकर्षक हो सकती है।
  - उपभोक्ता वैकल्पिक निवेश विकल्पों के रूप में स्टॉक, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
- **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता**:
  - रेपो दर कम होने से निवेश रिटर्न कम हो सकता है, जिससे पूंजी का बहिर्वाह हो सकता है।
  - कमज़ोर मुद्रा से आयात लागत बढ़ सकती है परन्तु निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो सकता है।
- **मुद्रास्फीति**:
  - कम दरों की वजह से बढ़ा खर्च कीमतों एवं मुद्रास्फीति बढ़ा सकता है।
  - मुद्रास्फीति RBI के 4% के लक्ष्य को पार कर सकती है और यह +/- 2% के दायरे में सीमित हो सकती है।

यह परिवर्तन वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के मध्य आया है, खास तौर पर व्यापार घर्षण और अमेरिका द्वारा आरोपित टैरिफ के कारण। यह बैंकिंग प्रणाली और व्यापक अर्थव्यवस्था में समग्र ब्याज दर वातावरण निर्धारित करेगा।

Samyak
An Institute For Civil Services